तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

लोकसभा अध्यक्ष से समयसीमा में फैसला लेने को कहा, सांसदों को जारी किया नोटिस

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई की। अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि इस मामले में तय समयसीमा के भीतर कार्यवाही पूरी की जाए। कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस भी जारी किया है। यह याचिका टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दायर की है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष को दल-बदल से जुड़ी याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की।

सुनवाई के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से औपचारिक नोटिस जारी नहीं करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह अदालत की मदद के लिए मौजूद हैं। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि मामला केवल नोटिस जारी करने का नहीं, बल्कि तय समयसीमा में कार्यवाही पूरी करने का है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) से जुड़ने वाले सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर लंबे समय से फैसला नहीं हुआ है। बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग गुट के रूप में मान्यता की मांग की है। टीएमसी का कहना है कि ये सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीतकर आए थे और किसी अन्य राजनीतिक संगठन से जुड़ना दल-बदल कानून के दायरे में आता है। बागी सांसदों के समूह ने 17 जून 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अलग गुट की मान्यता की मांग रखी थी। समूह की ओर से कहा गया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम करेगा। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लोकसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्यता याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय समय में पूरी करने की उम्मीद है।

नेतन्याहू का दावा- ईरान ने बेटे की हत्या की कोशिश की, सुरक्षा को बताया जरूरी

बोले- परिवार को मिली सुरक्षा ऐशोआराम नहीं, ट्रंप के बेटे को भी मिल चुकी धमकी

तेल अवीव, एजेंसीः इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान ने उनके परिवार को निशाना बनाया और उनके दो बेटों में से एक की हत्या की कोशिश की थी। उन्होंने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कही। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस बेटे को निशाना बनाया गया था और घटना कब हुई थी। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को दी जा रही सुरक्षा कोई ऐशोआराम नहीं है। यह बयान उन्होंने चुनाव से पहले परिवार और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए दिया। नेतन्याहू के दो बेटे याइर और अवनर हैं। बड़े बेटे याइर सोशल मीडिया पर अपनी राजनीतिक राय और दक्षिणपंथी विचारों के लिए चर्चा में रहते हैं। उन्हें विदेश में रहने के बावजूद इजराइली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट की सुरक्षा मिलने को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। 2018 से 2023 के बीच नेतन्याहू परिवार की सुरक्षा पर करीब 102 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई थी। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री के निजी आवासों को भी सुरक्षा जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है। 2022 से 2023 के बीच नेतन्याहू के यरुशलम और कैसरिया स्थित घरों की सुरक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। इजराइल में प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा देने की व्यवस्था है। जुलाई 2026 में एक समिति ने नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा को जीवनभर सुरक्षा देने का फैसला किया, जबकि दोनों बेटों को कम से कम पांच साल तक सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया। इससे पहले ईरान के सरकारी टेलीविजन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन को लेकर धमकी भरा कार्यक्रम दिखाए जाने की खबर सामने आई थी।

डिजिटल एसेट्स, सोना, तकनीक, एविएशन और शिपिंग क्षेत्र पर कार्रवाई, बढ़ सकता है आर्थिक दबाव

ईरान पर अमेरिका ने कसा शिकंजा, पांच प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में नए प्रतिबंध लागू

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था से जुड़े पांच प्रमुख क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन क्षेत्रों में डिजिटल एसेट्स, तकनीक, सोना, एविएशन और शिपिंग शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इन माध्यमों से ईरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां संचालित करता है और इन पर रोक लगाकर उसकी आय और व्यापारिक नेटवर्क को कमजोर किया जाएगा।

अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि कोई देश या कंपनी इन क्षेत्रों में ईरान के साथ ऐसा कारोबार करती है, जिससे उसे आर्थिक लाभ मिलता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन देशों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सामने अब दो रास्ते हैं। पहला, वह दुनिया से अलग-थलग होकर सीमित अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़े या दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल होने का रास्ता अपनाए।

अमेरिका के द्वितीयक प्रतिबंधों का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहता। यदि कोई विदेशी कंपनी ईरान के साथ प्रतिबंधित कारोबार करती है तो उस पर भी अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है।

अमेरिकी डॉलर और बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण के कारण ऐसी कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कारोबार करना मुश्किल हो सकता है।

अमेरिका ने ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार के आरोप में भारत की चार कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें पोर्टीज पार्टनर्स, सदाशिवा ओवरसीज, पीपी सॉफ्टटेक और प्रकृति इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि यह कदम ईरान की तेल से होने वाली आय और उससे जुड़े नेटवर्क पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है।

अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ईरान से तेल खरीद, चाबहार बंदरगाह परियोजना, डॉलर में भुगतान, ईरान के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों और कूटनीतिक संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। भारत ईरान के साथ संबंधों को अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक हितों के आधार पर देखता है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत को व्यापार और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

पीएम आवास के पास झुग्गियाँ हटाने का आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 6 हफ्ते की समयसीमा

प्रभावित परिवारों को 45 किलोमीटर दूर वैकल्पिक जगह पर जाने का निर्देश

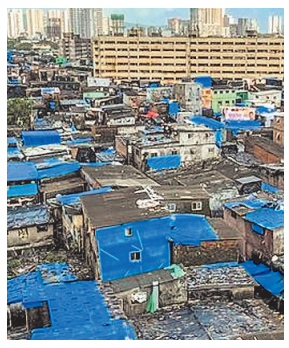

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित तीन झुग्गी बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यहां रहने वाले लोगों को छह सप्ताह के भीतर वैकल्पिक स्थान पर जाने के निर्देश दिए हैं। यह वैकल्पिक जगह मौजूदा स्थान से करीब 45 किलोमीटर दूर बताई गई है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तय समय सीमा के भीतर जमीन खाली नहीं की जाती है तो दिल्ली सरकार पुलिस की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकती है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को निर्धारित अवधि के अंदर वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित होना होगा। अदालत ने जमीन खाली कराने की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए यह मामला अदालत के सामने आया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमीन के उपयोग और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रभावित लोगों के स्थानांतरण और जमीन खाली कराने की प्रक्रिया को तय समय में पूरा करें। यदि तय अवधि में स्थान खाली नहीं किया गया तो प्रशासन कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकेगा।

पंजाब में भाजपा और अकाली दल गठबंधन की तैयारी तेज, सीट बंटवारे पर बातचीत आगे बढ़ी

भाजपा ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, अकाली दल ने ग्रामीण सीटों पर तैयारी घटाई

नईदुनिया ब्यूरो, लुधियानाः पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार, दोनों दल गठबंधन को फिर से अंतिम रूप देने के करीब हैं। इस बार भाजपा गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका में आ सकती है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। इसका संकेत इस बात से मिल रहा है कि अकाली दल ने कथित तौर पर अपने नेताओं से ग्रामीण क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर तैयारी कम करने को कहा है।

वहीं, भाजपा ने पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पंजाब दौरे के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सभी सीटों पर तैयारी करने को कहा। हालांकि, उन्होंने अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया। भाजपा और अकाली दल लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं। दोनों दलों का गठबंधन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर टूट गया था। बाद में केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए थे। हालांकि, भाजपा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को गठबंधन की चर्चाओं को लेकर कहा कि पार्टी फिलहाल किसी गठबंधन में नहीं है और अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

अमेरिकी सैन्य विमान रूस में उतरा

मॉस्को, एजेंसीः अमेरिकी वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान सी-17 ग्लोबमास्टर मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को के एक हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य विमान की रूस में लैंडिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार, विमान ने 23 अगस्त को वॉशिंगटन डीसी के पास स्थित जॉइंट बेस एंड्रयूज से उड़ान भरी थी। यह वही सैन्य अड्डा है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन भी तैनात रहते हैं। विमान को मॉस्को क्यों भेजा गया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। रूस ने कहा है कि उसे इस उड़ान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

मिसाइल तकनीक अब निजी कंपनियों को मिलेगी, बढ़ेगा स्वदेशी रक्षा उत्पादन

डीआरडीओ की तकनीक हस्तांतरण योजना मंजूर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय निजी कंपनियों को देने की मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य देश में मिसाइलों के उत्पादन को बढ़ावा देना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, डीआरडीओ योग्य निजी रक्षा कंपनियों को मिसाइल तकनीक उपलब्ध कराएगा। इन तकनीकों के माध्यम से कंपनियां देश में मिसाइल प्रणालियों का निर्माण कर सकेंगी। हालांकि, मंत्रालय ने अभी उन मिसाइलों की सूची जारी नहीं की है, जिनके उत्पादन की अनुमति निजी कंपनियों को मिलेगी। माना जा रहा है कि आकाश वायु रक्षा मिसाइल, अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और नाग टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल जैसी प्रणालियां इस पहल के तहत शामिल हो सकती हैं।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह व्यवस्था मिसाइल प्रणालियों के विकास से लेकर औद्योगिक उत्पादन तक के बदलाव को आसान बनाएगी। इससे रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और तकनीकी भागीदारों की भागीदारी बढ़ेगी।

अमेरिका में 2 लाख विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द करने की तैयारी

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिकी सरकार करीब 2 लाख विदेशी नागरिकों के बिजनेस वीजा और टूरिस्ट वीजा रद्द करने की तैयारी कर रही है। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा सकती है, जो बी1 और बी2 वीजा पर अमेरिका पहुंचे और बाद में वहीं रहने के लिए शरण आवेदन करने लगे। अमेरिकी विदेश विभाग आने वाले हफ्तों में इस संबंध में घोषणा कर सकता है। यदि यह कार्रवाई होती है तो इसे अमेरिका के इतिहास में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वीजा रद्द करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया माना जाएगा।

अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा कि कुछ लोग पर्यटन या व्यापार के उद्देश्य से अमेरिका आते हैं, लेकिन बाद में वहां रहने के लिए शरण की मांग करते हैं। सरकार ऐसे मामलों की समीक्षा कर रही है। वीजा रद्द होने का मतलब यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति को तुरंत अमेरिका से बाहर भेज दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का शरण आवेदन लंबित है तो वह कुछ समय तक अमेरिका में रह सकता है, लेकिन उसका बी1 या बी2 वीजा मान्य नहीं रहेगा। विदेश विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 18 महीनों में करीब 1.75 लाख वीजा रद्द किए जा चुके हैं। इनमें अपराध के आरोपों, दोषसिद्धि और अमेरिकी नीतियों के खिलाफ गतिविधियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

मानसून का कहर *अस्पतालों और घरों में घुसा पानी, गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम लागू; उड़ानें भी प्रभावित...*

काशी और दिल्ली में जलभराव से हालात खराब, भारी बारिश का अलर्ट

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश का असर लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। वाराणसी में 15 घंटे हुई लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। गलियां तालाब में बदल गईं और कई घरों में पानी घुस गया।

बीएचयू अस्पताल में भी घुटनों तक पानी भरने की स्थिति बनी, जहां मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई। राजधानी के कई प्रमुख इलाकों जैसे एम्स फ्लाईओवर, कनॉट प्लेस, आईटीओ और आरके पुरम में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-गुरुग्राम को जोड़ने वाले एनएच-48 पर महिपालपुर के पास लंबा जाम लग गया। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। बारिश के कारण सोमवार को करीब 390 उड़ानें देरी से चलीं, 15 उड़ानों को डायवर्ट किया गया और 26 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। हरियाणा के गुरुग्राम में कई इलाकों में तीन फीट तक पानी भरने के बाद मंगलवार को सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया। इससे पहले सोमवार को कई स्कूल बसें घंटों तक जलभराव में फंसी रहीं।

बिहार के भागलपुर में राघोपुर-नरकटिया तटबंध टूटने से करीब 10 हजार लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड और केरल समेत 15 राज्यों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।